

कृषि विभाग की खरीदी धनंजय मुंडे के कार्यकाल में नियमों के अनुसार ही थी-हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना

रिपोर्ट: जमीर काज़ी । मुंबई

मुंबई हाईकोर्ट ने तत्कालीन कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के कार्यकाल में राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए खरीदे गए पूरक कृषि सामान की प्रक्रिया को पूरी तरह वैध करार दिया है। कोर्ट ने इस निर्णय को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति संदीप वी. मर्णे की खंडपीठ ने सुनाया।

सत्यमेव जयते : धनंजय मुंडे की प्रतिक्रिया

धनंजय मुंडे ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाला यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। इसके विरोध में मुझ पर कई आरोप लगाकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ। लेकिन आज न्यायालय ने सत्य को सामने लाकर न्याय किया है और यह सिद्ध किया है कि वह निर्णय बिल्कुल सही था। मुंडे ने अपने बयान का अंत सत्यमेव जयते कहकर किया।



जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब कृषि मंत्रालय धनंजय मुंडे के पास था। १२ मार्च २०२४ को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, बैटरी से चलने वाले स्प्रेयर, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, मेटालिहाइड कीटनाशक और कपास भंडारण के लिए बैम्स - इन पाँच वस्तुओं को महाराष्ट्र एगो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे खरीदी कर किसानों को वितरित करने

का निर्णय लिया गया था।

हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों ने धनंजय मुंडे और कृषि विभाग पर 'घोटाले' का आरोप लगाते हुए बदनाम करने की कोशिश की थी। इस निर्णय के खिलाफ एपी स्प्रेयर्स टीम एसोसिएशन और उमेश भोले सहित तीन किसानों ने अलग-अलग याचिकाएं और एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें इन वस्तुओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (उद्द) योजना

से बाहर करने का विरोध किया गया था।

राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि २०१६ की उद्द योजना और २०२३-२४ का विशेष कार्य योजना - दोनों ही योजनाएं अपने आप में अलग हैं और इनका उद्देश्य केवल किसानों का हित है। विशेष कार्य योजना का मकसद किसानों को केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उत्पादन, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से समग्र सहयोग देना है, जो पूरी

तरह से उचित है।

इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उद्द योजना और विशेष कार्य योजना का आपस में कोई संबंध नहीं है। सरकार ने यह एक नीतिगत निर्णय लिया है, जिसमें अदालत का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल अपने व्यापारिक हितों के लिए अदालत पहुंचे थे और सरकार की नीति पर गलत टिप्पणी करके बदनामी करने की कोशिश की,

इसलिए उनकी जनहित याचिका खारिज की जाती है।

विशेष रूप से याचिकाकर्ता तुषार पाडगिलवार ने न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए फोरम शॉपिंग की, जिसके लिए उन पर १ लाख रुपये का दंड लगाया गया है। यह जुर्माना चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट विधि सेवा प्राधिकरण में जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व वसूली के आदेश

दिए जाएंगे। पाडगिलवार ने पहले मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन जब उन्हें यह लगा कि फैसला उनके खिलाफ आ सकता है, तो उन्होंने अपनी मुख्य मांगें वापस ले लीं। इसके बाद उन्होंने नागपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के नाम पर कुछ किसानों को सामने रखकर झूठे बिल और फर्जी सबूतों के सहारे कोर्ट को भ्रमित करने का प्रयास किया। इस पर भी अदालत ने टिप्पणी की है।

राहुल गांधी का आरोप: चुनाव आयोग की मदद से हुआ मतदाता धोखाधड़ी, कांग्रेस के पास १००% सबूत

नई दिल्ली, २४ जुलाई (संवाददाता)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी के पास चुनाव आयोग द्वारा समर्थित मतदाता धोखाधड़ी के १००% सबूत मौजूद हैं। उन्होंने दो ट्रक शब्दों में कहा कि हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं और इस मामले को आगे लेकर जाएंगे।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि

कांग्रेस को चुनाव में हुए कथित फर्जीवाड़े के ऐसे सबूत मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से लाखों वोट गलत तरीके से डाले या ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इन सबूतों के साथ देश की जनता के सामने आएगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करने

वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई केवल एक पार्टी की नहीं, बल्कि देश की जनता और लोकतंत्र की है।

इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और



निराधार बताया है।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट और तकनीकी विश्लेषण के साथ सबूतों को सार्वजनिक करने जा रही है। इसमें चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों, ईवीएम और मतदाता सूची से जुड़ी विमर्शितियों को सामने लाया जाएगा।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव २०२४ के नतीजों को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, और अब कांग्रेस के इस सीधे आरोप ने राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है।

दिल्ली के अन्नू खान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया

सिंगापुर में १२ और १३ जुलाई को आयोजित National Masters -athletics -ssociation (NM--) की टीम ने सिंगापुर में आयोजित Singapore Masters International Track Field Championship २०२५ में भारत का नाम रोशन कर दिया। दस ज्यदा देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, दिल्ली मजनु दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, और अब कांग्रेस के इस सीधे आरोप ने राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है।



रजत पदक जीता। इस जीत के साथ, अन्नू खान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और भारत का नाम रोशन किया है। दिल्ली और मजनु का टीला के लोगों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। सिंगापुर से लौटते ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई

अड्डे पर अन्नू खान के साथ पूरी टीम का भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाएं, ढोल-नागाड़े, नाचते-गाते पूरा एयरपोर्ट जश्न के रंग में डूब गया। सुरेश शर्मा (पूर्व पुलिस महानिरीक्षक पंजाब पुलिस एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन) ने बताया कि यह दृश्य किसी विजयी सेना की घर वापसी जैसा था। इंडियो एयरलाइंस की फ्लाइट में भी टीम की उपलब्धि की घोषणा की गई, जिस पर यात्रियों ने जोरदार तालियों से टीम का स्वागत किया।

बीड-नगर-मुंबई रेल्वे जलद शूर हो, बारशी नाका थांबा के लिए कोशिश

गडकरी और रेल मंत्री वैष्णवने बंजरग सोनावने को दिखाई सकारात्मकता

बीड: संवाददाता

जिले के विभिन्न राष्ट्रीय महामार्गों के कार्यों को शीघ्र पूरा करने, निर्माण कार्यों के दौरान हुए तकनीकी दोषों को सुधारने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जैसे कई मुद्दों को लेकर बीड के सांसद बजरंग सोनवणे ने २४ जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। लगातार किए जा रहे उनके इस प्रयास को देखते हुए मंत्री गडकरी ने उनकी पीठ थपथपाकर सराहना की।

इसी दिन सांसद सोनवणे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर बीड जिले की रेलवे परियोजनाओं से संबंधित समस्याएं उनके समक्ष रखीं। रेल मंत्री ने इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए



सकारात्मक रुख दिखाया और शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया।

गडकरी से मुलाकात के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दे: सांसद सोनवणे ने शेगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय महामार्ग के परतूर-माजलगाव हिस्से के अंतर्गत सादोळा (ता. माजलगाव) में अधूरे



पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। माजलगाव-केज हिस्से में खराब हिस्सों की मरम्मत तथा तकनीकी खामियों को दूर करने, धारूर घाट में प्रस्तावित बायपास सड़क का निर्माण, बर्दापूर-लोखंडी सावर्गाव फोर-लेन सड़क का कार्य जल्द शुरू करने और केज-कळंब मार्ग पर मांजरा

नदी पर पुल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर कार्य पूर्ण करने की मांग की।

इसके अलावा, पैठण-पंढरपुर तथा अहमदपुर-मांजरासुंबा-पाटोदा मार्ग की समस्याओं को तात्कालिक रूप से सुलझाने और प्रस्तावित अन्य कार्यों को भी मंजूरी देने की मांग की गई।

सोनवणे ने छत्रपति संभाजीनगर-बीड-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर गेवराई तालुका के गडी गांव में बने पुल व मार्ग के कारण हुई दुर्घटना में छह युवकों की मौत के लिए विभागीय तकनीकी दोषों को जिम्मेदार ठहराते हुए दोष तय करने और मृतकों के परिवार को सहायता देने की भी पुरजोर मांग की।

इन सभी बिंदुओं पर मंत्री गडकरी ने व्यक्तिगत ध्यान देने का आश्वासन दिया

और संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, आपका बीड जिले के विकास के लिए किया जा रहा प्रयास और संघर्ष सराहनीय है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा के मुख्य मुद्दे:

बजरंग सोनवणे ने आहल्यानगर-बीड-परळी रेलवे प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित १० रोड ओवर ब्रिज और ढोलेवस्ती (बीड) रोड अंडरपास के कार्यों को शीघ्र शुरू करने की मांग की।

इसके साथ ही, बीड शहर के बाशीनाका रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को रुकवाने की मंजूरी देने, अंबाजगाई तालुका के घाटनांदूर स्टेशन पर भी स्टॉपिज प्रदान करने, और

बीड-आहल्यानगर-मुंबई (उड्ड) के बीच नियमित ट्रेन सेवा शीघ्र शुरू करने की मांग भी रखी। इन मांगों पर मंत्री वैष्णव ने सकारात्मकता दिखाते हुए शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

सादोळा पुल निर्माण को लेकर आंदोलन की पृष्ठभूमि: शेगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत सादोळा (माजलगाव) में पुल और सड़क का निर्माण अधूरा है। भूमि संबंधी विवादों के चलते कार्य अटका हुआ है। कुछ दिन पूर्व सादोळा के नागरिकों ने इस मुद्दे पर अनशन भी किया था। सांसद सोनवणे ने २४ जुलाई को यह मामला सीधे नितिन गडकरी के समक्ष उठाया। इस पर गडकरी ने कहा, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह समस्या जल्द सुलझाई जाएगी।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

भाजपा सांसद दुबे से सवाल पूछने वाली बहादुर महिला सांसदों का कांग्रेस की ओर से अभिनंदन

महाराष्ट्र विरोधी बयान की तीव्र निंदा

रिपोर्ट: विशेष संवाददाता, मुंबई
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के महाराष्ट्र के खिलाफ अपमानजनक बयान से राज्य की अस्मिता को ठेस पहुंची है। संसद भवन की लॉबी में उन्हें सीधे सवाल पूछने वाली कांग्रेस की रणरागिनी महिला सांसद - वर्षा गायकवाड़, प्रतिभा धानोरकर और शोभा बच्छाव - इन तीनों का गुरुवार को मुंबई कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक अभिनंदन किया गया।
इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन सावंत ने किया। प्रमुख प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस, अनुसूचित जाति विभाग



के मुंबई अध्यक्ष कचरू यादव, महासचिव महेंद्र मुणगेकर, प्रवक्ता निजामुद्दीन राईन, राजेश इंगले, मंदाप पवार, आनंद यादव, के.पी. सिंह, राजेश टेक आदि भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में बोले हुए सचिन सावंत ने कहा, महाराष्ट्र के स्वाभिमान का

महाराष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक चेतना पर हमला किया है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि संसद जैसे पवित्र स्थान पर ऐसे अपमानजनक वक्तव्य देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान दुबे के बयान का विरोध करते हुए यह संकल्प लिया गया कि - महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वालों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। मुंबई कांग्रेस की ओर से इन तीनों साहसी महिला सांसदों को गौरवपत्र देकर सम्मानित करने का निर्णय भी इस अवसर पर लिया गया।

आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का आक्रोश; बीड जिला परिषद के सामने जोरदार आंदोलन, प्रशासन भी हुआ परेशान!



बीड । प्रतिनिधि
आंगनवाड़ी सेविकाओं की लंबित मांगों को लेकर गुरुवार, २४ जुलाई को बीड जिला परिषद के समक्ष महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी सेविका व मदतनिस महासंघ की ओर से तीव्र प्रदर्शन और धरना आंदोलन किया गया। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सेविकाओं ने प्रशासन की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की। अंततः जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्वयं आंदोलन स्थल पर आकर सेविकाओं का निवेदन स्वीकार करना पड़ा।
सेविकाओं ने आरोप लगाया कि ऋड (एफ.आर.एस.)

प्रणाली के माध्यम से ढकठ (टी.एच.आर.) वितरण के दौरान तकनीकी समस्याओं - जैसे मोबाइल हैंग होना, ओटीपी न आना, नेटवर्क का न होना - की वजह से कार्य का बोझ काफी बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया है।
इसके साथ ही सेविकाओं ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं, जिनमें शामिल हैं:
पेंशन, ग्रैच्युइटी और अक्टूबर २०२४ से जून २०२५ तक का प्रोत्साहन भत्ता तुरंत वितरित किया जाए। प्रोत्साहन भत्ते को नियमित मानधन में शामिल कर सेविकाओं को १५,००० और सहायिकाओं

को ८,५०० मासिक मानधन दिया जाए।
आंगनवाड़ी का समय सुबह ९:३० से दोपहर २:३० तक ही लागू रखा जाए, जबन ४ बजे तक की ड्यूटी की शर्त हटाई जाए।
भगवान देशमुख, कमल बांगर, दत्ता देशमुख, सचिन आंधळे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बीड जिले के विभिन्न हिस्सों की आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं शामिल हुईं। सेविकाओं ने प्रशासन की उपेक्षा पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। भारी बारिश के बावजूद आंदोलित महिलाओं का जोश और संघर्ष प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। अंत में, स्वयं जिला कार्यक्रम अधिकारी ससे ने आंदोलन स्थल पर आकर सेविकाओं का निवेदन स्वीकार किया।

हैप्पी बर्थडे पंकजाताई-सैकड़ों छात्रों ने एक सुर में दी शुभकामनाएं

ना. पंकजा मुंडे के जन्मदिन पर चित्रकला प्रतियोगिता को जबरदस्त प्रतिसाद

परळी बैजनाथ
हैप्पी बर्थडे पंकजाताई - ऐसा एक सुर में सैकड़ों विद्यार्थियों ने कहा और ना. पंकजा मुंडे ने भी उतने ही उत्साह के साथ थैंक यू कहते हुए बच्चों की शुभकामनाएं स्नेहपूर्वक स्वीकार कीं। यह अवसर था उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित चित्रकला स्पर्धा का। प्रतियोगिता के दौरान ना. पंकजाताई मुंडे ने वीडियो कॉल के माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद साधा। इस दौरान लगभग ११०० से अधिक विद्यार्थियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, शिक्षक और पालक



उपस्थित थे।
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व पशुसंवर्धन मंत्री तथा जालना जिले की पालक मंत्री ना. पंकजा मुंडे के जन्मदिन के अवसर पर २१ से २७ जुलाई के बीच परळी शहर भाजपा की ओर से विभिन्न सामाजिक सेवा उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत गुरुवार, २४ जुलाई को विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, नेत्र परीक्षण, मोतियाबिंद शस्त्रक्रिया, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और युवाओं के लिए मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया था।
भाजपा शहराध्यक्षा उमा समशेट्टे ने बताया

के साथ संपन्न हुए हैं।
चित्रकला प्रतियोगिता के प्रमुख अतिथि के रूप में वैद्यनाथ बैंक के चेयरमैन विनोद सामत, माऊली आधाव, महादेव ईटके, पत्रकार धनंजय आढाव, पत्रकार महादेव शिंदे, संभाजी मुंडे, संदीप लाहोटी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभिक भागण में अश्विन मोगरकर ने बताया कि परळी शहर की ४६ स्कूलों के ११५० विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने कहा कि लोकनेता ना. पंकजा मुंडे के जन्मदिवस के अवसर पर उनके विचारों के अनुरूप सामाजिक कार्य भाजपा द्वारा किया जा रहा

है, जिससे पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच रही है। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानोबा सुरवसे ने किया और आभार प्रदर्शन अनिश अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर महादेव ईटके, नितीन समशेट्टी, मोहन जोशी, अरुण पाठक, अनिश अग्रवाल, सुशील हरंगुळे, सारिका कुरिल, चंदा ठोंबरे, शैलजा आदोडे, प्रशांत कराड, किशोर केंद्रे, योगेश पांडकर, पवन मोदणी, विजय बुंदेले, राहुल घोबाळे, बडू नाना कोरे, राजेश कौलवर, श्रीपाद शिंदे, दिलीप नेहरकर, उमेश निळे, अच्युत जोगदंड, अस्लम शेख, योगेश मुंडे, विराज गिते, निलेश गिते आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद कोकाटे पर होगा निर्णय: अजित पवार

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई से
विधानमंडल सत्र के दौरान ताश (रमी) खेलने का वीडियो वायरल होने और स्वयं अपनी सरकार को 'भिखारी' कहने से विवादों में धिरे कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे पर पहली बार उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजित पवार ने कहा, अब तक मेरी कोकाटे जी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सोमवार या मंगलवार को उनसे भेंट होगी और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

कोकाटे के वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। बीते चार दिनों से विपक्ष का रुख काफी आक्रामक है। किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से कोकाटे की तीव्र आलोचना हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार ने कहा, मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह घटना सभागृह के भीतर हुई है। विधानमंडल परिसर की जवाबदारी सभापति राम शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर के अधीन आती है। उन्होंने जांच शुरू की है। मेरी कोकाटे जी से अब तक कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। उनका कहना है कि वे खेल नहीं रहे थे। सोमवार या मंगलवार को उनसे बात कर सच्चाई सामने लाई जाएगी।



पवार ने आगे कहा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद हमने सभी मंत्रियों को समझाया था कि हमें राज्य की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर बोलना और व्यवहार करना चाहिए। हमने अपने-अपने दलों के नेताओं को इस बाबत निर्देश दिए थे।
उन्होंने यह भी कहा कि, पिछली बार भी जब कोकाटे ने अनुचित बयान दिया था, तब भी हमने चेतावनी दी थी। दोबारा ऐसा हुआ तो फिर से समझाया। अब वे कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब तक वास्तविकता स्पष्ट नहीं होती, निर्णय नहीं लिया जाएगा।
'पेनड्राइव और वीडियो की धमकी देना बंद करें': अजित पवार
जब पत्रकारों ने रोहित पवार के खिलाफ वीडियो जारी करने की धमकी के संदर्भ में पूछा, तो अजित पवार ने कहा,

विपक्ष का काम ही यही है। हर बार कहते हैं कि वीडियो हैं, पेनड्राइव हैं - ये धमकियाँ देना बंद करें। एक बार सब कुछ सार्वजनिक कर दीजिए। सिर्फ बातें और सुर्खियाँ बनाने से कुछ नहीं होता। जनता को भी सच्चाई जानने दीजिए। पहले की सरकारों में भी यही सब कहा जाता था। हर कोई पेनड्राइव दिखाता फिरता था। सभी संशय के घेरे में आते हैं। इनमें चार मंत्री, कुछ आईपीएस अधिकारी और राजनीतिक लोग शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति कहा जाए तो सब पर शक होता है। एक बार वास्तविकता सामने आनी चाहिए। अगर सबूत हैं तो उन्हें पेश करें, पुलिस प्रणाली अपनी तरह से जांच करेगी।
सरकार की तरफ से कोई बिल बकाया नहीं: अजित पवार
मध्यवर्ती ठेकेदार संघटन ने यह आरोप लगाया कि जनजीवन योजना के तहत ठेकेदार हर्षल पाटिल ने सरकार के बकाया भुगतान के चलते आत्महत्या की। इस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा,
हर्षल पाटिल मुख्य ठेकेदार नहीं था, उसने अपने मित्र से सब-कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इसलिए सरकार पर भुगतान का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार की तरफ से कोई बिल लंबित नहीं है, सभी प्रक्रियाधीन हैं।

कोकण सहित पुणे, सातारा घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट

विशेष संवाददाता
मुंबई:
राज्य में बारिश का जोर तेज हो गया है। गुरुवार को मुंबई, ठाणे और कोकण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। अगले २४ घंटों के लिए रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों के साथ-साथ पुणे घाट, सातारा घाट और कोल्हापुर घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने जानकारी दी है।



भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र ने ठाणे, मुंबई शहर व उपनगर, रायगढ़, रत्नागिरी, पांचवर् और सिंधुदुर्ग जिलों के समुद्री तट पर २४ जुलाई २०२५ की शाम ५:३० बजे से २६ जुलाई २०२५ की रात ८:३० बजे तक समुद्र

को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही समुद्र के कटाव और ऊँची लहरों के किनारों से टकराने की चेतावनी दी गई है, जिस कारण सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

गडचिरोली जिले के गोमणी गांव में अचानक बड़े कोलपल्ली नाले के बाढ़ के पानी में ग्रामसेवक उमेश धोडरे फंस गए थे, लेकिन पुलिस विभाग और स्थानीय बचाव दल ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

मुंबई शहर और उपनगरों को पानी की आपूर्ति करने वाले मोडक सागर, मध्य वैतरणा और तानसा जलाशयों से क्रमशः २०४३.७४, २११८.९५ और ३३१५.२५ क्यूसेक पानी का विसर्ग (छोड़ना) किया जा रहा है। संभावित आपदा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (छउठक) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (डउठक) को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा राज्य आपातकालीन केंद्र ने जानकारी दी है।

गाज़ा में मानव संकट पर भारत को गहरी चिंता, तत्काल युद्धविराम की मांग

संयुक्त राष्ट्र, २४ जुलाई
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने गाज़ा में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए तत्काल युद्धविराम की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवथनेनी हरीश ने अपने बयान में कहा कि गाज़ा में हो रही घटनाएं मानवता के विरुद्ध संकट हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए सभी पक्षों को संयम और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।
गुरुवार को सुरक्षा परिषद में गाज़ा पर चर्चा के दौरान भारत

ने स्पष्ट कहा कि अब संक्षिप्त युद्धविराम पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थायी युद्धविराम की आवश्यकता है ताकि लाखों प्रभावित लोगों तक बिना बाधा के मानवीय सहायता पहुंच सके। भारत ने यह भी मांग की कि गाज़ा में बंधकों की तत्काल और सुरक्षित रिहाई की जाए।
भारत ने दो टुक शब्दों में कहा कि गाज़ा में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, अस्पताल बंद हो रहे हैं, और नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। थक के मुताबिक ९५% से अधिक अस्पताल या तो बंद हैं या

सीमित रूप से काम कर रहे हैं। भारत ने इस पर गहरी चिंता जताई।
भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दो-राष्ट्र समाधान को ही दीर्घकालिक समाधान बताया और कहा कि इस दिशा में बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा, गाज़ा में जो हो रहा है वह सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ संकट है। हम सभी पक्षों से तत्काल युद्धविराम, बंधकों की

रिहाई, और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति की मांग करते हैं।
भारत ने इस संकट के मद्देनजर खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य मानवीय राहत सामग्री गाज़ा भेजने की पहल की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के इस रुख को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे गाज़ा में मानवीय सहायता की आपूर्ति और शांति स्थापना के प्रयासों को बल मिलेगा।